Situation arising out of mass Killings in Bara village in Gaya district of Bihar

श्री रजनी रंजन साहू (बिहार) : उप सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसी घटना की ओर सदन का ध्यान इस विशेष उल्लेख के जरिए आकर्षित करना चाहता हूं जो सिर्फ हृदय-विदारक ही नहीं, मानवता के नाम पर एक कलंक है।

महोदया, बिहार के मध्य भाग में गया एक जिला है। इस जिला के बारा गांव में 12 फरवरी, 1992 की रात को 39 निर्दोष व्यक्तियोंकी नृशंस हत्या अमानवीय ढंग से सामूहिक रूप से कर दी गई। इससे बिहार राज्य के लोग ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लोग क्षुब्ध हैं एवम् स्तब्ध हैं। इस क्रूर एवं हृदय-विदारक घटना की घोर निन्दा इस सदन के माध्यम से मैं करना चाहता हूं। माननीय गृहमंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि सारा सदन इस क्रूर और निन्दनीय घटना में मेरा साथ दे और गृह मंत्रालय से दरख्वास्त करे कि ऐसी घटना दुबारा वहां या कहीं भी देश में न हो इस बात का वे आश्वासन दें। मुझे अफसोस इस बात का है, कि माननीय गृह मंत्री जी वहां जाकर भी वहां नहीं पहुंच पायें, उसमें कई बातों की झलक है, कई बातें सामने आती हैं। लोग इतने उत्तेजित थे और वहां की सरकार के विरोध में जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी उत्तेजना की वजह से वहां का वातावरण ऐसा भयानक था जिसमें न जाना ही उचित था। लेकिन वहां जाने पर, "गया" जाने पर, उन्हें जो जानकारी मिली और मुझे भी जो जानकारी मिली उससे साफ जाहिर है कि बिहार में हिंसा उग्र रूप धारण कर चुकी है। सामूहिक हत्याओं एवम नरसंहार की घटनाओं में बढ़ोत्तरी होती जा रही है। राज्य में 1990 से लेकर अब तक 41 सामूहिक हत्याओं की घटनाएं हुई हैं जिनमें कुल मिलाकर 256 व्यक्ति मारे गए हैं। इसी "गया" जिले के "इमामगंज डुमरिया" में 80 से अधिक अल्पसंख्यकों की हत्या हुई थी। 23 दिसम्बर को "बारा" से करीब 3 किलोमीटर दूर "नरसेमारीन" गांव में 16 से अधिक हरिजनों की हत्या हुई थी। प्रशासन उन हरिजनों को कोई सुरक्षा नहीं दे पाया। इस घटना के बाद से पिछले तीन महीनों से विभिन्न निजी सेनाओं के बीच चल रही दुश्मनी के परिणाम स्वरूप निरीह एवं निर्दोष जनता को बचाने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। मैं केन्द्र सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इन निजी सेनाओं पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए।

बिहार के मध्य हिस्से में निजी सेना पिछले कई वर्षों से प्रशासन अपने हाथ में ले चुकी है। इस सेना का प्रादुर्भाव जहां तक मेरी जानकारी है, आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के कारण हुआ। और भी कई कारण हैं। आज यह सेना एक विकराल रूप धारण कर चुकी है और जातीय उन्माद पर उतर आई है।

उपसभापति महोदया, वहां की घटनाएं ऐसी हैं कि तुलना करने पर पता चलता है कि 1990 के मुकाबले 1991 में सामूहिक हत्याओं में ढाई गुना वृद्धि हुई है। 1992 के एक-डेढ़ महीने के भीतर 51 लोग मारे गए हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो न जाने मारे जाने वाले लोगों की संख्या कहां पहुंच जाएगी। सामूहिक हत्याओं के अलावा एक के बाद एक नरसंहार की घटनाओं की कड़ी बढ़ती जा रही है। प्राध्यापक, डाक्टर और सम्भ्रांत जनों का अपहरण फिरौती के लिए किया जा रहा है। लूट-पाट तो आम बात बन गई है। एक-एक गांव जातीय विद्वेष में झुलस रहा है। लगता है कि बिहार में जनता को सुरक्षा और अभयदान देने वाली कोई सत्ता नाम की चीज नहीं रह गई है। वहां आर्थिक स्थिति, अर्जन और विकास कार्य ठप्प हैं। (समय की घंटी) उपसभापति महोदया, एक मिनट। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : इनको बोलने दिया जाए। बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस पर सदन में बहस कराई जाए।

1.00 P. M.

श्री रजनी रंजन साहू : बिहार में अपराध महज कानून और व्यवस्था विकास बनकर रह गयी है, बल्कि आठ जिलों में तो इसने महामारी का रूप धारण कर लिया है। इन जिलों में वामपंथी उग्रवादियों ने बाहर के उग्रवादियों के साथ अपना तालमेल बैठा लिया है, जहां से उन्हें विदेशी अस्त्र-शस्त्र उपलब्ध कराये जाते हैं। प्राप्त रिपोर्टस से पता चलता है कि एम०सी०सी० उपद्रवकारी गया, पलावू और हजारी बाग के ग्रामीण क्षेत्रों में अपना अड्डा बनाते जा रहे हैं। इन जिलों के गांव सामान्यतः अपराधी गिरोह की गिरफ्त में आ चुके हैं और यह अपराधी तत्व दहशत पैदा करने के लिए, अपनी धाक जमाने के लिये निर्मम हत्यायें करते जा रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, इसलिए इस सब बातों की जानकारी कराना उपसभापति महोदया, हमारे लिये आवश्यक था। जनता की जानमाल और निर्दोष व्यक्तियों की हिफाजत करना सरकार का प्रथम दायित्व है। बिहार में स्थिति इतनी चिंतनीय और खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची है... **(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : गृह मंत्री जी तो वहां जा ही नहीं पाये।

श्री रजनी रंजन साहू : जाते कैसे ? आप अगर जानना चाहते हैं मैं उस बात को नहीं कहना चाहता हूं। वहां की सरकार गृह मंत्री जी की सुरक्षा नहीं कर पायी कि वे वहां तक पहुंच पायें। वहां इनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए बिहार सरकार सक्षम नहीं थी कि यह वहां जा सकें। यह तो बिहार सरकार के लिए शर्म की बात है। गृह मंत्री की सुरक्षा करना उनका दायित्व है। गृह मंत्री जी के वहां पहुंचने पर पुलिस पदाधिकारी कहते हैं कि आप गांव में न जायें। अब आप यह बताइये कि बिहार सरकार के लिये इससे शर्म की बात और कुछ हो सकती है ?

SHRI P. UPENDRA (Andhra Pradesh) : It is a very serious allegation. Home Minister is here. It is a reflection on the State Government. Let the Home Minister say whether it is a fact. It is a very serious matter. If the Home Minister of India cannot visit a State because his security is not ensured, how can they ensure security of the citizens?

श्री राम अवधेश सिंह : यह सदन एक विस्तृत बहस की मांग करता है।

श्री शांति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : पहले उसकी निन्दा तो करिये।

श्री रजनी रंजन साहू : बिहार की स्थिति इतनी चिंतनीय और खतरनाक है और ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है कि उसमें केन्द्र सरकार को अब अपनी जवाबदेही लेनी चाहिए। मेरा ऐसा विचार है है कि जो घटनायें हो रही हैं उन घटनाओं के क्रम में सक्षम रूप से केन्द्र सरकार को उसको रोकने के लिए अपना योगदान या उसमें अपना सहयोग जैसे भी हो, देना चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ आपका बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री शांति त्यागी : उपसभापति महोदय मैं भी एसोशिएट करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : गृह मंत्री को बिहार की सरकार सुरक्षा नहीं दे पायी। माननीय उपसभापति महोदया गृह मंत्री जी यहां मौजूद हैं। साहू जी ने बिहार सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि गृह मंत्री जी वहां नहीं पहुंच सके, जिसका कारण था कि बिहार की सरकार उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दे पायी। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस देश को जानकारी करायें कि साहू जी ने जो आरोप लगाया है वह सत्य है या नहीं ? क्या वास्तविक रूप में बिहार की सरकार आपको सुरक्षा नहीं

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

दे पाई ? दो-दो केंद्रीय मंत्री वहां पर बेकार थे। दूसरे सीताराम केसरी जी थे और इत्तफाक से मैं उसी दिन वहां पर था और दूसरे दिन मैं स्वयं बारा गांव गया।

श्री रजनी रंजन साहू : आप पहले उसकी तो निंदा करो।... (**व्यवधान**)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN) : It is a fact. What the hon. Member has stated is hundred per cent correct. In fact, I had specially gone in order to see the conditions myself and have some kind of an assessment made and here after if there was anything which needed to be done, I was inclined to do the same. But I cannot deny the fact that having gone to the outskirt of the village, the officers of the Bihar Government came and told me: that 'it will not be proper to go further and advised to return you better go back' I cannot violate what the State Government representatives tell me and that is why I had to come back and that evening itself fly back to Delhi.

श्री अवधेश सिंह : उपसभापति महोदया, एक मिनट। जरा मुझको सम्बद्ध करने दीजिए न, हमारे स्टेट का सवाल है।

श्री रजनी रंजन साहू : यह आप पीछे बोलिये न, कम से कम शर्म की बात तो बोलिये... (**व्यवधान**)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं तो सहमत हूं, मैंने तो वहां सुना, मैं ठीक उसी दिन वहीं था। दूसरे दिन बारा गांव गया। वहां लोगों ने मुझे बताया कि गृह मंत्री को वहां पर राज्य सरकार के परामर्श से जाने नहीं दिया गया, क्योंकि अधिकारियों ने कहा कि खुद गृह मंत्री जी की जिंदगी वहां खतरे में पड़ सकती है। अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्री की जिंदगी खद खतरे में है ... (**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह : उपसभापति महोदया, मैं इस विशेष उल्लेख से अपने को सम्बद्ध करता हूं और मैं आपकी सेवा में चन्द शब्द कहना चाहता हूं क्योंकि मैं भी 22 तारीख को वहां जाने के लिए निकला था और मुझे भी नहीं जाने दिया गया। तो मैंने जो स्टडी किया, मैंने जो विश्लेषण किया उस घटना का और वहां की परिस्थिति का, उसका कुछ आकलन मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

महोदया, आप इस बात का अंदाजा लगा सकती है कि कितनी विस्फोटक स्थिति उस इलाके में है कि भारत सरकार के गृह मंत्री को वहां नहीं जाने दिया गया यह अपने आप में ही स्पष्ट बात है जिससे आप वहां की परिस्थिति का अंदाजा लगा सकती हैं। भारत सरकार के गह मंत्री को किसने नहीं जाने दिया, यह अलग विवाद का विषय है। शायद उनकी पार्टी के लोगों ने ऐसी व्यूह रचना की या वहां का प्रशासन इतना निकम्मा साबित हुआ, इसके बारे में तो अलग बात की जा सकती है लेकिन यह बात तो साफ है कि वहां स्थिति इतनी भयावह है कि उसका अंदाजा लगाना साधारण तौर से मुश्किल है। उसके दो कारण हैं।

महोदया, वहां का जो इलाका है, उसके 5–7 जिले हैं, जिनका जिक्र किया साहू जी ने, वहां का समाज इतना सताया गया है खासकर हरिजन, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग, कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं यहां बयान नहीं कर सकता कि किस तरह का सामाजिक उत्पीड़न हुआ था। आज वहां उसके विरुद्ध लड़ाई हो रही है और हिंसा से सामाजिक उठान को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह हिंसा से दबाव के खिलाफ उठान की भी प्रक्रिया जारी है और हिंसा से दबाने की प्रक्रिया भी जारी है। यह क्यों हुआ? इसलिए कि पिछले 44 वर्षों में अहिंसा की कोख से जन्मी हुई कांग्रेस सरकार ने अहिंसा को महत्व नहीं दिया। जब अहसिक संघर्ष से हम लोग सामाजिक बदलाव के लिए लड़ते थे तो

ये हम लोगों को पीटते भी थे और हम लोगों की बात नहीं सुनते थे और हम लोग कहते थे कि... (व्यवधान)

उपसभापति : राम अवधेश जी, आप पालिसी पर न बोलें। जो असल मुद्दा है कि लोगों की हत्या हुई, उसके विषय में अगर कोई जानकारी दे रहे हैं तो दीजिए। पालिसी पर मत बोलिए।

श्री राम अवधेश सिंह : महोदया, बारा हत्याकांड जघन्य अपराध है, घोर निंदनीय है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए लेकिन इस पर केवल एक वाक्य या दो वाक्य कह देने से काम नहीं चलेगा क्योंकि यह जो डेढ़ महीने पहले घटना घटी, उसमें 10 आदमी मारे गए। फिर उसके जवाब में ये 36 आदमी मारे गए। जब सत्येन्द्र बाबू मुख्य मंत्री थे तो उनके राज में भी ऐसी घटना घटी थी और 10 आदमी उसमें मारे गए थे। फिर उसके जवाब में करीब-करीब 56 राजपूत लोगों की हत्या हो गई। वह मुख्यमंत्री ठाकुर थे, तो भी उनकी रक्षा नहीं हो सकी। यह जात-पात का सवाल नहीं है। जो कहते हैं कि यह जात की वजह से हुआ और लालू यादव वहां पर है मुख्य मंत्री इसलिए लोगों की हत्या हुई, यह बात नहीं है।

वहां ऐसी विस्फोटक परिस्थिति बन गई है कि दबाव भी हिंसा से हो रहा है और उठान भी हिंसा से हो रहा है। उसके लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। हम कह सकते हैं, मांग कर सकते हैं कि... (व्यवधान)

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA (Punjab) : Madam, are Special Mentions over ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Ram Awadhesh Singh, we are not having discussion. Mr. Upendra please.

श्री राम अवधेश सिंह : मैडम, मुझे खत्म करने दीजिए। मैं यह कह रहा हूं कि वहां ऐसी स्थिति में कम से कम 18 कंपनियों सी०आर०पी० और पैरा मिलिट्री फोर्सेज की भेजी जायें ताकि बिहार में जो एक्सप्लोसिव जगहें हैं, वहां उनको लगाय जाए और उसका खर्चा भारत सरकार खुद उठाए क्योंकि भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वहां ला एंड आर्डर कायम हो। पूरे बिहार को तो लूट लिया ... (व्यवधान)

उपसभापति : बस अब आप बैठ जाइये... (व्यवधान)

Stoppage of funds by Industrial Reconstruction Bank of India to Sick Industrial Units on RBI directions

SHRI P. UPENDRA (Andhra Pradesh) : Madam, there are disquieting reports that the sick industrial units in the private sector will not be eligible for funds from the Industrial Reconstruction Bank of India here afterward. Reserve Bank of India has sent a circular already that the IRBI should function as a commercial unit and the earlier procedure of 60 per cent of the funds being used for the revival of the sick units in the private sector and 40 per cent for healthy units should be done away with. That means, the very basic character of this IRBI is going to be changed. There is a Parliament Act in this connection. The Act is called the IRDI Act, which also requires to be amended. I do not know whether the Government is coming forward with an amendment. How the very existence of this Bank is in jeopardy because now BIFR is being assigned with some of the tasks which were earlier being performed by the IRBI. I do not know whether the Government wants to close down this IRBI. They have not made it clear. Recently, the Government has decided to set up this National Renewal Fund. It is not known whether the sick units in the private sector will be eligible to receive assistance from this Fund also. That has not made very clear. There is a great anxiety among the